



रणथम्भौर के जोन नम्बर-2 में शिकार को पकड़ने के चक्कर में दो टाइगरस की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों टाइगर एक सांभर को अपना शिकार बनाना चाहते थे। इस रोमांचक घटना ने रणथम्भौर भ्रमण करने आये पर्यटकों को बेहद गदगद कर दिया। रणथम्भौर में इन दिनों बाघों की बढ़ती संख्या के कारण उनमें टैरिटरियल फाइट की घटनायें काफी बढ़ गई हैं।

## एफ.आई.आर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की। क्योंकि ये जबदस्ती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में घुस गए थे। उन्होंने कहा, यह "क्रिमिनल ट्रेसपास" है। हम उनके निलम्बन व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हैं।

सुरजेवाला ने मांग की कि टी.वी. कैमरा को ई.डी. में आने दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह खुरद ई.डी. के साथ बैठकर राहुल गांधी से सवाल करें। सुरजेवाला ने कहा कि, देश को पता तो चले कि भाजपा के पास सिर्फ झूठा और फर्जी दुष्चारा है और राहुल के पूछने के लिए एक भी सवाल नहीं है।

# रणथम्भौर में दो बाघों की आपस में जोरदार भिड़ंत

सवाई माधोपुर, 15 जून (निस)। रणथम्भौर के जोन नंबर 2 में बुधवार को सुबह की पारी के दौरान सांभर के शिकार को लेकर दो टाइगरस में भिड़ंत हो गई।

इन दोनों की भिड़ंत देखकर पार्क भ्रमण पर गए पर्यटक गदगद हो गए। भिड़ंत में टाइगर टी-120 योद्धा के भारी पड़ने पर बाघिन टी-84 एरोहेड शिकार छोड़कर चली गई। पार्क भ्रमण पर आए पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में इस भिड़ंत का वीडियो कैद कर लिया। रणथम्भौर में टाइगरस की बढ़ती तादाद के

दोनों टाइगर एक सांभर के शिकार को लेकर आपस में उलझ पड़े।

इस लड़ाई में टाइगर-120 भारी पड़ गया और बाघिन को शिकार को छोड़कर वहां से निकलना पड़ा।

पर्यटकों ने इस भिड़ंत की तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कीं।

कारण आप दिन इनके आपसी संघर्ष देखने को मिल रहे हैं।

रणथम्भौर के टाइगर इससे पूर्व भी कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। बाघिन

टी 84 एरोहेड ने समर्पण कर दिया और शिकार छोड़कर वहां से चली गई। इसके बाद टाइगर टी-120 ने आराम से बैठ कर सांभर को अपना भोजन बनाया।

# दिल्ली में सचिन पायलट सहित कांग्रेस विधायक हिरासत में लिए गए

## जयपुर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फूँका गया

जयपुर, 15 जून (का.प्र.)। दिल्ली में चल रहे आंदोलन में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति रही। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं को एआईसीसी मुख्यालय नहीं जाने दिया गया तो उनकी पुलिस से काफी बहस हुई।

इससे पहले सचिन पायलट समर्थकों और पुलिस के बीच काफी देर तक तनावनी की स्थिति रही। बाद में पायलट सहित एआईसीसी के सचिव कुलदीप इंद्रौरा, विधायक मुकेश भाकर, वेदप्रकाश सोलंकी, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर नरेला थाने ले जाया गया। हिरासत के बाद सचिन पायलट ने कहा कि "हम अपनी पार्टी के दफ्तर जाना चाह रहे थे, कि हमें पार्टी मुख्यालय जाने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। क्या हम अपने पार्टी मुख्यालय भी नहीं जा सकते, यह लोकतंत्र में गलत है। यह निंदनीय है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है, कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है।"

दिल्ली में पुलिस 2 दिन से कांग्रेस मुख्यालय में भी नेताओं-कार्यकर्ताओं के नहीं जाने दे रही है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ और एआईसीसी मुख्यालयों में पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ अब कांग्रेस ने सभी राज्यों का राजधानियों में राजभवनों के घेराव का फैसला किया है। जयपुर में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन और सभा करेंगे।



दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट व अन्य नेताओं को जब कांग्रेस मुख्यालय (नई दिल्ली) में प्रवेश करने से रोका तो दोनों पक्षों में काफी तनावनी की स्थिति बन गई। बाद में वहीं से पुलिस ने पायलट को हिरासत में ले लिया।

इसके बाद अगले दिन 17 जून को कांग्रेस की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे।

इधर राजस्थान में राहुल गांधी पर ईडी के जरिए किए जा रहे जुल्म एवं तानाशाही के विरोध में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप सिंह खारियावास के

निर्देशानुसार बुधवार को कलैंकरी सक्रिय पर कांग्रेस महामंत्री एवं प्रवक्ता मनोज मुद्गल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुद्गल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी तथा कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन जैसे बड़े मुद्दों से देश

की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर बेवजह मुकदमे के जरिए ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स की छापेमारी करके इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के कांग्रेस दफ्तर जाने से रोक रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं।

गुरुवार को सभी प्रदेशों में राजभवन घेरेगी कांग्रेस, 17 जून को जिला मुख्यालय पर होगा विरोध प्रदर्शन।

कलैंकरी सक्रिय के प्रदर्शन में पार्षद बृजेंद्र तिवारी, उमेश शर्मा, अजरहरीदन सहित भीमराज प्रजापति, रूबी खान, शहीद तिरंगा, विनोद बुनकर, शदाब खान, दौलत सैनी, प्रदीप चौधरी, धर्मेन्द्र शर्मा, सोनू बागवान, सुधांशु दिल्ली, मानवेंद्र मानपुरा, अनिल खंडेलवाल, सुधीर शर्मा आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस की ओर से दिल्ली में जारी आंदोलन अब प्रदेशों की राजधानी से होता हुआ जिला स्तर पर शुरू होगा इसके तहत 16 जून को कांग्रेस सभी प्रदेशों के राजभवन घेराव केंद्र की मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और 17 जून को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा।

# फर्जी मैडिकल रिपोर्ट

जयपुर, 15 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मारपीट से जुड़े एक प्रकरण में पुलिस और मैडिकल ऑफिसर की मिलीभगत से दो मैडिकल रिपोर्ट देने और पहली रिपोर्ट में चोट को गंभीर बताते और दूसरी में जानलेवा बताने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने करौली जिला कलैंक्टर से कहा है कि वह मामले में आरएएस स्तर के अधिकारी से जांच कराए। जांच अधिकारी पता लगाए कि किन हालातों में पुलिस ने मैडिकल ऑफिसर से राय मांगी और मैडिकल ऑफिसर ने अलग रिपोर्ट क्यों दी। अदालत ने मामले की जांच 60 दिन में पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि मामले में भ्रष्टाचार हुआ है तो वह सबके सामने आना

चाहिए। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश भरत सिंह व दो अन्य की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में दो अलग-अलग मैडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर गंभीर प्रतिक्रिया की।

अदालत को संदेह है कि, फर्जी मैडिकल रिपोर्ट की बिसात पर परिवादी पर जानलेवा हमला करने का मामला बनाया जा रहा है। इसलिए अदालत ने जिला कलैंक्टर को आदेश दिए कि वो वरिष्ठ आर.ए.एस. अफसरों के साथ मिलकर मामले की जांच करायें।

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है। मामला केवल मारपीट से जुड़ा है,

लेकिन पुलिस ने मैडिकल ऑफिसर की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमले की धारा जोड़ी है। मामले में तीन

महला ने कहा कि पुलिस व मैडिकल विभाग ने मिलीभगत की है। पहली मैडिकल रिपोर्ट 31 दिसंबर 2021 की है, जिसमें अंगुली की चोट को गंभीर बताया है। वहीं 18 जनवरी 2022 को पुलिस के आग्रह पर मैडिकल ऑफिसर ने उसी चोट को जानलेवा बताया है। याचिकाओं में कहा गया कि मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए।

गौरतलब है कि करौली जिले के मासलपुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ पहले मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मैडिकल ऑफिसर की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमले की धारा जोड़ दी।

महला ने कहा कि पुलिस व मैडिकल विभाग ने मिलीभगत की है। पहली मैडिकल रिपोर्ट 31 दिसंबर 2021 की है, जिसमें अंगुली की चोट को गंभीर बताया है। वहीं 18 जनवरी 2022 को पुलिस के आग्रह पर मैडिकल ऑफिसर ने उसी चोट को जानलेवा बताया है। याचिकाओं में कहा गया कि मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि करौली जिले के मासलपुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ पहले मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मैडिकल ऑफिसर की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमले की धारा जोड़ दी।

# राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को फोन किया

## राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे व नवीन पटनायक से राष्ट्रपति उम्मीदवार के संबंध में मंत्रणा की

नई दिल्ली, 15 जून। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा ने बुधवार को विपक्षी नेताओं से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव से बात की। उन्होंने राकांपा प्रमुख शरद पवार और बसपा प्रमुख मायावती से भी बात की।

सूत्रों के मुताबिक, राजनाथ सिंह ने एनडीए की साथी जदयू से भी संपर्क किया। उन्होंने नवीन पटनायक को भी फोन लगाया। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर सहमति बनाने की लेकर चर्चा हुई। इससे पहले भाजपा ने रविवार को राजनाथ सिंह और पार्टी

अध्यक्ष जेपी नड्डा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने खड़गे, बनर्जी और

कि विपक्षी नेताओं ने राजनाथ सिंह से भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जानना चाहा। इससे पहले ममता बनर्जी की ओर से बुलाई

बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा राजट अधिसूचना के बाद 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दाखिल किए गए 11 नामांकनों में से एक नामांकन अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज हो गया।

यादव सहित कुछ अन्य दलों के नेताओं से भी फोन पर बात की। राजनाथ सिंह से विपक्ष के नेताओं से बात ऐसे वक्त पर की है, जब विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक अहम बैठक बुलाई थी। सूत्रों ने बताया

गई विपक्षी दलों की बैठक में बुधवार को कई दलों के नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों

के मुताबिक पवार द्वारा प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद विपक्ष के संभावित उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम भी सामने आये। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट, आजसू और निर्दलीय के नेताओं से बात की। वहीं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में हुई विपक्ष की बैठक में बीजू जनता दल (बीजद), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों की अनुपस्थिति से भाजपा ने राहत की सांस ली है। वहीं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया।

## पवार राष्ट्रपति का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 29 जून है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई है।

बुधवार की मीटिंग में 17 पार्टियों ने भाग लिया-यथा कांग्रेस, टी.एम.सी., सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम.), सी.पी.आई.एम.एल., आर.एस.पी., शिव सेना, एन.सी.पी., आर.जे.डी., एस.पी., नेशनल कॉन्फ्रेंस, पी.डी.पी., जे.डी. (एस), डी.एम.के., आर.एल.डी., आई.यू.एम.एल. और जे.एम.एम.। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयराम रमेश और ए.आई.सी.सी. महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मीटिंग में भाग लिया। लेकिन उन्होंने किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया। खड़गे को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीटिंग में भाग लेने के लिए अधिकृत किया था। मीटिंग में आए नेताओं में टी.एम.सी. की ममता बनर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डी.एम.के. के टी.आर.बालू, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और आर.जे.डी. के मनोज झा थे।

# ई.डी. प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

## मध्यप्रदेश की कांग्रेस नेता ने ई.डी. प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को गैरकानूनी बताया

नई दिल्ली, 15 जून (वार्ता)। नेशनल हेराल्ड विवाद मामले में कोटोस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बीच महिला कांग्रेस की एक सदस्य ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर ने अपनी याचिका में मिश्रा के कार्यकाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम के विस्तार के लिए 17 नवंबर 2021 को पारित आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।

करके लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसी वजह से मिश्रा का कार्यकाल गत वर्ष 17 नवंबर को बढ़ा दिया गया था।

ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि मिश्रा की सेवानिवृत्ति नवंबर 2020 में होनी थी, लेकिन उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। याचिका में दावा किया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से मात्र दो दिन पहले नवंबर 2021 में कार्यकाल बढ़ाया गया था।

ठाकुर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच का हवाला देते अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार विरोधियों की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले 10 वर्षों से जांच कर रही है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि, केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ई.डी. का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि, इसी वजह से मिश्रा का कार्यकाल गत वर्ष 17 नवंबर को बढ़ा दिया गया था।

निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश रद्द करने की गुहार लगाई है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग

# श्रीलंका व पाकिस्तान की तरह ईरान भी कंगाली की कगार पर

## ईरान की ईकॉनमी पस्त होने के कारण रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें इतिहास के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं

नई दिल्ली, 15 जून। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकॉनमी पस्त है। ये सभी भारत के पड़ोसी देशों में से हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था भी डगमगाती दिख रही है।

बुनियादी वस्तुओं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसी बीच ईरान के श्रम, कल्याण और सामाजिक मामलों के मंत्री होज्जतुल्ला अब्दुलमालकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई

सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का जोरदार विरोध कर रहे हैं।

महंगाई पर हो रहे भारी विरोध के कारण ईरान के श्रम, कल्याण और सामाजिक मामलों के मंत्री होज्जतुल्ला अब्दुलमालकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई

सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का जोरदार विरोध कर रहे हैं।

मांग कर रहे थे। ईरान परमाणु समझौते और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर जारी गतिरोध के बीच ईरानी रियाल की कीमत गिरकर नए निचले स्तर पर आ गई है।

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होज्जतुल्ला के इस्तीफे के बाद से इब्राहिम सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। सरकार ने मोहम्मद हादी जाहेदी वफा को कार्यवाहक मंत्री बनाया है। रिटायर्ड लोगों के साथ ही शिक्षक,

जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने परमाणु समझौते को लेकर ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए।

राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अमेरिका से बातचीत शुरू हुई तो ईरान की उम्मीद बढ़ी लेकिन लेकिन विनया में एक साल की गहन बातचीत के बाद मार्च में बातचीत बंद हो गई। ऐसे में ईरान की इकॉनमी गिरती चली गई।

## 'मंकीपॉक्स बीमारी का नाम बदलें'

जिनेवा, 15 जून (वार्ता)। दुनिया में तेजी से फैलते मंकीपॉक्स वायरस को कुछ वैज्ञानिकों के स्टिंगमाटाइजिंग (कर्त्तिक्रिया किया जाना या किसी को दोषारोपण करना) कहे जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी अब महाभारी का नाम बदलने का फैसला किया है।

'न्यूयॉर्क पोस्ट' ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम गेब्रेयियस ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर के अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों के साथ मंकीपॉक्स वायरस का नाम बदलने के काम में जुटा हुआ है। हम जितनी जल्दी हो सके नए नाम की घोषणा करेंगे।

दरअसल, 30 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों से मिले एक पत्र के बाद डब्ल्यूएचओ ने यह कदम उठाया है। पत्र में नाम को तत्काल रूप से बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पत्र में लिखा गया, निरंतर बातचीत और मुद्दे पर लगातार विचार-विमर्श करने के बाद यह जरूरी समझा जा रहा है कि हम इसे भेदभाव रहित और गैर कर्त्तिक्रिया नाम दें।

इसमें कहा गया, वायरस का नाम बार-बार अफ्रीका से जोड़ा जा रहा है और इसका नामकरण अफ्रीकी प्रुथुभूमि की तर्ज पर होना निष्कूलक गलत है, यह भेदभाव और किसी को कर्त्तिक्रिया कराना दिखाता है। मीडिया में भी वायरस से संबंधित जितनी भी तस्वीरें हैं, उनमें से अधिकतर में अफ्रीकी नजर आ रही है।

# ममता बनर्जी द्वारा आहूत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.) सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री की राइड प्रमुख को लेकर अपनी स्वयं की आकांक्षाएं हैं। अतः उन्होंने आवेशित होकर कहा कि ममता ने शरद पवार के नाम का संकेत देकर एक्टरफा कदम उठाया है।

वास्तव में यह पूरी मीटिंग की ही दुःखती राह है क्योंकि कई नेताओं ने बनर्जी द्वारा शरद पवार का नाम, किसी विचार-विमर्श के बिना अचानक उछालने पर आपत्ति जताई। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के इस कदम ने उन्हीं की छवि धूमिल की क्योंकि उनके चयनित व्यक्ति शरद पवार ने स्वयं ही उनका ऑफर ठुकरा दिया और बताया जाता है कि इसे ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ने के इच्छुक नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी जो अब पंजाब और दिल्ली, दोनों में सत्तारूढ़ है, उम्मीद के अनुसार एक बार फिर मीटिंग से दूर रही। दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी

मजबूत करने की ममता की शैली को लेकर उनके घोर आलोचक आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अन्य राज्य स्तरीय चुनावों के लिए ममता से विचार-विमर्श करने के विचार को झिड़क दिया। आप ने कहा कि सुझाए गए नामों को देखने के बाद ही वह अपना स्टैण्ड फाइनल करेगी और निर्णय लेगी। इस प्रकार से वह बनर्जी के नेतृत्व वाली विचार-विमर्श मशीनरी से दूर रहेगी।

यहां तक कि भाजपा के पूर्व सहयोगी अकाली दल ने भी बाद में दूरी बना ली। उसने मीटिंग में भाग नहीं लिया। शीर्ष स्तर पर भाग लेने की बात तो छोड़िए उसने मीटिंग में अपना प्रतिनिधि भेजने तक पर विचार नहीं किया।

इसी तरह से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मीटिंग से दूर रहे और उन्होंने अपने पते नहीं खोले। स्टालिन भी अपना रूतबा कायम करना चाहते हैं और ममता के आगे झुकना नहीं चाहते।